निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं। इन उद्योगों की श्रेणियों का विवरण निम्नलिखित है:

उद्योग की श्रेणी	अनुपालन न करने वाले उद्योगों की संख्या
1. कागज एवं लुग्दी	53
2. डिस्टिलरी	8
3. चीनी मिल	9
4. औषध उद्योग	7
5. इंजीनियरिंग उद्योग	16
6. वस्त्र उद्योग	10
7. रासायनिक उद्योग	1
8. दुग्ध उद्योग	1
9. अन्य	28

(घ) नदियों में बहिःस्रावों के निसस्सारण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) उद्योगों के लिए बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं।

(2) दोषी इकाइयों के विरुद्ध, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

(3) लघु उद्योगों के समूहों में सामूहिक बहिःस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(4) कतिपय अधिसूचित प्रदूषण निगरानी एवं नियंत्रण उपकरणों के लिए सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में छूट प्रदान की जाती है।

(5) यमुना नदी में देश के प्रमुख नदियों के कुछ अत्यधिक प्रदूषित भागों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा यमुना कार्य योजना एवं राष्ट्रीय नदी कार्य योजना शुरू की गई है।

Pressure from P-8 countries on India to sign NPT

909. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether pressures are being mounted by the P-8 Group of developed countries on Government to change its stand on NPT and missile development;

(b) whether the Canadian Government has in a demarche demanded such a change; and

(c) what strategy, if any, has been formulated to deal with this development?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) The Canadian Prime Minister, in his capacity as Chairman of the G-8 group of countries, had written a letter dated 9 September expressing concerns about the effect of missile deployment and further development of nuclear capability on security in South Asia.

(c) Government has conveyed categorically that it does not share the assessement of the G-8 on this matter. Government remains committed to improving relations with all its neighbours. Where differences in perceptions exist, India is willing to engage in bilateral consultations in order to develop a better understanding of each other's concerns. Government keeps the security situation of India constantly under review particularly in the light of developments in the neighbourhood and is committed to taking all necessary measures designed to cope with any threat that may be posed to the security of the nation.